हम भारत के लोग

बनाम

भारत सरकार

भारत सरकार के खिलाफ संसदीय लोकतंत्र पर प्रहार करने और कमज़ोर बनाने का आरोपपत्र

आरोपों की सूची

क्रमांक	आरोप
1.	संविधान के अनुच्छेद 93 का उल्लंघन, लोक सभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं
2.	पूर्ण कार्यकाल लोक सभा में सत्रों की सबसे कम संख्या, संसद को अपनी मर्जी के अनुसार नियंत्रित करना, सरकार के जवाबदेही के लिए अवसरों को कम करना
3.	संसदीय निगरानी से बचने के लिए और संविधान पर धोखाधड़ी करते हुए अध्यादेशों को बढ़ाना और पुनर्प्रस्तुत करना
4.	बिना चर्चा के बिल लाना, विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति में बिना चर्चा के बिलों को पारित करना, अलोकतांत्रिक तरीके से
5.	कानून निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, उचित सार्वजनिक परामर्श नहीं करना, पूर्व-विधिक परामर्श नीति का उल्लंघन करना और बिलों को स्थायी समितियों को नहीं भेजना
6.	उचित निगरानी के बिना बजट पारित करना, वित्त बिल में समस्यात्मक प्रावधानों को शामिल करना, जैसे कि चुनावी बॉन्ड्स (electoral bonds)
7.	शीतकालीन सत्र 2023 में अभूतपूर्व संख्या में विपक्षी सांसद निलंबित, वस्तुतः विपक्ष-विहीन संसद ने विवादास्पद विधेयक पारित किए
8.	सरकार प्रश्नों के साथ असहज, विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए प्रश्नों को हटा दिया जाता है, मंत्रालय प्रश्नों का उपयोगी उत्तर नहीं देते हैं

सबूतों का विस्तारपूर्ण विश्लेषण

आरोप - संविधान के अनुच्छेद **93** का उल्लंघन, लोक सभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं

सबूत- 17 जून 2019 को 17वीं लोकसभा की शुरुआत के बाद से लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं चुना गया है। आजादी के बाद यह पहली बार है कि संविधान के अनुच्छेद 93 के आदेश के बावजूद लोकसभा का कार्यकाल उपाध्यक्ष का पद खाली रहने के साथ पूरा होगा, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करेगी, जितनी जल्दी हो सके| चूँकि अध्यक्ष आमतौर पर सरकार का नामित व्यक्ति होता है, इसलिए उपाध्यक्ष परंपरागत रूप से विपक्ष का नामित व्यक्ति होता है। लोकसभा में सत्तारूढ़ दल की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए जानबूझकर नामांकन में देरी करि गयी है।

आरोप - पूर्ण कार्यकाल लोक सभा में सत्रों की सबसे कम संख्या, संसद को अपनी मर्जी के अनुसार नियंत्रित करना, सरकार के जवाबदेही के लिए अवसरों को कम करना

सबूत-

● इससे पहले 16वीं लोकसभा (2014-19) में अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान सबसे कम बैठकें हुई थीं - 331 बैठकें। हालाँकि, 17वीं लोकसभा में अब सबसे कम बैठकें होने की संभावना है - लगभग 278 (2024 के निर्धारित बजट सत्र सहित)। यह एनडीए (NDA) के पहले पूर्ण कार्यकाल - 13वीं लोकसभा (1999-2004) के दौरान 423 बैठकों की तुलना में भी काफी कम (लगभग 34% कम बैठकें) है।

● 2020 के दौरान, कोविड (COVID) का बहाना बनने के कारण, भारतीय संसद केवल 33 दिनों के लिए सत्र में थी। दुनिया भर में कई अन्य लोकतंत्रों में आभासी संसद सत्र (virtual parliament session), बहसें और यहां तक कि दूरस्थ मतदान भी हुआ, लेकिन भारतीय संसद वर्ष के अधिकांश समय बंद रही। 2020 में शीतकालीन सत्र हुआ ही नहीं. यहां तक कि संसद की स्थायी समितियां भी पहली कोविड लहर के चरम के दौरान कोविड के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया, प्रवासी पलायन आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक नहीं कर सकीं क्योंकि उन्हें वस्तुतः (virtually) मिलने की अनुमति नहीं थी।

● राज्यों के विधानसभा चुनाव संसद सत्र छोटा करने का बहाना बन गये हैं। 2017 और 2022 में गुजरात जैसे कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों के कारण शीतकालीन सत्र में देरी हुई और उसे छोटा कर दिया गया। 2018 और 2023 में, राजस्थान और तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों में चुनावों के कारण फिर से शीतकालीन सत्र में देरी हुई और उसे छोटा कर दिया गया।

● जब सरकार सत्र के लिए अपना एजेंडा पूरा कर लेती है, तो वह सत्र को तय समय से पहले स्थगित करवा देती है। 2020 से 2022 के बीच लगातार सात सत्र तय समय से पहले खत्म हुए। 2023 में विशेष सत्र और शीतकालीन सत्र भी तय समय से पहले समाप्त हो गए। जब कोई सत्र निर्धारित समय से पहले समाप्त हो जाता है, तो शेष दिनों के लिए पूछे गए सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, सांसद सदन में सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने का अवसर खो देते हैं। इस प्रकार, संसद केवल सत्ता में पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच बनकर रह जाती है, न कि लोगों के ज्वलंत मुद्दों पर बहस करने के लिए।

आरोप - संसदीय निगरानी को छोड़ते हुए और संविधान पर धोखाधड़ी करते हुए अध्यादेशों **(ordinance)** को बढ़ाना, अधिनियमों को पुनर्प्रस्तुत करना

सबूत–

● यूपीए (UPA) II सरकार के तहत, 2004-14 के बीच 61 अध्यादेश जारी किए गए थे। 2014 से 2021 के बीच 76 अध्यादेशों से ये रिकॉर्ड टूट चुका है.

● भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश तीन बार (2014-15) प्रख्यापित किया गया था। शत्रु संपत्ति (संशोधन और सत्यापन) अध्यादेश एक ही वर्ष (2016) में 5 बार प्रख्यापित किया गया था - एक तरह का रिकॉर्ड। अध्यादेशों को दोबारा जारी करना संविधान के साथ धोखाधड़ी है, क्योंकि अध्यादेश बनाने की शक्ति का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में अस्थायी प्रावधान करने के लिए किया जाता है।

● तीन कृषि कानूनों को पहली बार अध्यादेश के रूप में लाया गया था जब लोग 2020 में कोविड की पहली लहर से बचने में व्यस्त थे।

● 2023 में, दिल्ली के एनसीटी सरकार (संशोधन) अध्यादेश को जारी किया गया था जिसका उद्देश्य दिल्ली सरकार को 'सेवाएं' पर नियंत्रण प्रदान करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना था। यह वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के असफलता का संकेत है, जो कानून के अनुसार अधिक लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से अपना कार्य करने में असमर्थ है।

आरोप - बिना चर्चा के बिल लाना, विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति में बिना चर्चा के बिलों को पारित करना, अलोकतांत्रिक तरीके में

सबूत-

● 17वीं लोकसभा में अब तक (21 दिसंबर, 2023 तक), लोकसभा में 86 विधेयक और राज्यसभा में 103 विधेयक 2 घंटे से कम के बहस समय के साथ पारित किए गए हैं।

● 2023 के शीतकालीन सत्र में, संसद के दोनों सदनों से विपक्षी सांसदों के सामूहिक निलंबन के बाद, केवल 3 दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा लगभग 14 विधेयकों को मंजूरी दे दी गई, जिसमें विपक्ष ने या तो भाग नहीं लिया या न्यूनतम भागीदारी दी। .

● 2023 के शीतकालीन सत्र में 3 आपराधिक विधेयकों पर बहस के दौरान लोकसभा में 34 सांसदों ने भाग लिया, जिनमें से 25 अकेले भाजपा के थे और इसी तरह राज्यसभा में विधेयक पर बोलने वाले 40 सांसदों में से 30 अकेले भाजपा के थे।

● 2020 के मानसून सत्र में, चूंकि विपक्षी सांसदों ने फार्म बिल के जबरन पारित कराने के बाद कार्यवाही का बहिष्कार किया, उस सत्र में पारित 27 विधेयकों में से 15 के लिए, विपक्षी सांसद किसी एक या दोनों सदनों में अनुपस्थित थे।

● 2021 के मानसून सत्र में, जब विपक्ष ने विरोध किया क्योंकि सरकार ने पेगासस जासूसी कांड और किसानों के विरोध पर बहस की उनकी मांग को रोक दिया, तो लोकसभा ने विरोध के बीच 18

विधेयकों को मंजूरी दे दी, प्रत्येक पर औसतन केवल 15 मिनट खर्च किए। कुछ बिल तो 5-6 मिनट में ही पास हो गए।

● 2023 के मानसून सत्र में, केवल एक सप्ताह में लोकसभा ने 7 विधेयकों को केवल 21 मिनट के औसत समय के साथ पारित किया। विवादास्पद वन संरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में 33 मिनट के भीतर पारित हो गया, केवल 4 सांसद बोले। लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर सिर्फ 40 मिनट तक बहस हुई, सिर्फ 8 सांसद ही बोले। राज्यसभा में डीपीडीपी बिल पर सिर्फ 50 मिनट तक बहस हुई, इस दौरान किसी भी विपक्षी सांसद ने हिस्सा नहीं लिया. विपक्ष मणिपुर हिंसा पर विरोध प्रदर्शन कर रहा था और बहस की मांग कर रहा था.

● 2023 के मानसून सत्र में एक नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ, जब राज्यसभा ने फार्मेसी (संशोधन) विधेयक को मात्र 3 मिनट के भीतर पारित कर दिया। अगले दिन, लोकसभा ने दो विधेयकों - केंद्रीय जीएसटी संशोधन और एकीकृत जीएसटी संशोधन विधेयक - को 3 मिनट के भीतर मंजूरी दे दी!

● कई बार अंतिम समय में विधेयकों को एजेंडे में शामिल किया जाता है।

- 2017 में, शत्रु संपत्ति (संशोधन और मान्यकरण) विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया था, जब अधिकांश विपक्षी सांसद इस आश्वासन पर चले गए थे कि उस दिन विधेयक पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 2019 में, जम्मू और कश्मीर पुनर्व्यवस्थान विधेयक पूरी तरह से अचानक प्रस्तुत किया गया और सांसदों को विधेयक को पढ़ने या विश्लेषण करने का कोई अवसर दिए बिना राज्यसभा में पारित कर दिया गया।

- 2021 के मानसून सत्र में, कुल 11 पूरक सूचियां जारी की गईं, जिनमें से 9 सिर्फ राज्यसभा में थीं और इनमें से 6 का उद्देश्य प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों को प्रस्तुत करना या पारित करना था, जिससे सांसदों को विधेयकों पर अध्ययन, विश्लेषण, और चर्चा करने के लिए पर्याप्त अवसरों से वंचित कर दिया गया। वास्तव में, आखिरी दिन संविधान (105 वां संशोधन) विधेयक और दो और विधेयक राज्यसभा के कार्यसूची में शामिल किए गए थे, जिसके लिए सांसदों को संशोधन प्रस्तुत करने के लिए केवल एक घंटा मिला।

- 2021 के शीतकालीन सत्र में, सरकार ने सांसदों को बहस के लिए तैयारी करने का कोई समय दिए बिना, उसी दिन चुनाव कानून संशोधन विधेयक (जो अन्य चीजों के अलावा आधार-मतदाता पहचान पत्र जोड़ने का प्रावधान करता है) को पारित करने पर जोर दिया। अगले दिन ही इसे राज्यसभा में बहस के लिए ले जाया गया और सांसदों ने आरोप लगाया कि उन्हें पहले से सूचित नहीं किया गया था।

- तीन आपराधिक विधेयक भी मानसून सत्र, 2023 के आखिरी दिन अचानक से पेश किए गए थे।

- 2023 के शीतकालीन सत्र में दूरसंचार विधेयक को भी अंतिम समय में एजेंडे में शामिल कर पेश किया गया।

- चुनाव से पहले सरकार के आखिरी संसद सत्र में 5 फरवरी 2023 को ही 3 विधेयकों को अंतिम समय में एजेंडे में शामिल कर पेश किया गया था।

- आखरी संसद सत्र में, सरकार के मूल रूप से प्रस्तावित एजेंडे में केवल 3 विधेयकों का उल्लेख था, लेकिन सरकार ने न केवल 3 नए विधेयक पेश किए, जो मूल रूप से एजेंडे में शामिल नहीं थे, बल्कि पिछले सत्रों से लंबित दो और विधेयकों को आगे बढ़ा दिया, जो कि थे भी नहीं उसके एजेंडे का हिस्सा.

आरोप - कानून निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, उचित सार्वजनिक परामर्श नहीं करना, पूर्व-विधिक परामर्श नीति का उल्लंघन करना और बिलों को स्थायी समितियों को नहीं भेजना

सबूत-

● 2009-2014 के बीच सभी बिलों में से 71% को स्थायी समितियों को भेजा गया था, 2019 के बाद से, केवल 16% बिलों को स्थायी समिति को भेजा गया है।

● संसद में पेश किए गए 301 में से केवल 74 यानी 24.5% विधेयकों को 2014 और 2021 के बीच परामर्श के लिए प्रसारित किया गया था। इन 74 विधेयकों में से, कम से कम 40 को 30 दिनों तक प्रसारित नहीं किया गया था, जैसा कि पूर्व-विधान परामर्श नीति में निर्दिष्ट है।

● अधिक विवादास्पद विधेयक संयुक्त संसद समितियों को भेजे जाते हैं (क्यूंकि सरकार तय करती है कि इस समिति में किसे रखा जाए)। 2014 के बाद से निम्नलिखित विधेयक विपक्षी सांसदों की अध्यक्षता वाली संबंधित स्थायी समितियों के बजाय भाजपा सांसदों की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसद समिति को भेजे गए:

- भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक
- नागरिकता संशोधन विधेयक
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक
- वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक
- जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक

● समितियाँ जनता से टिप्पणियाँ आमंत्रित नहीं कर रही हैं और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले उचित परामर्श नहीं ले रही हैं। जन विश्वास विधेयक पर संयुक्त संसद समिति ने जनता से टिप्पणियाँ आमंत्रित नहीं कीं। भाजपा सांसद की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की स्थायी समिति, जो तीन आपराधिक विधेयकों का अध्ययन कर रही थी, ने जनता से टिप्पणियां आमंत्रित नहीं कीं। कई विपक्षी सांसदों ने असहमति नोट प्रस्तुत करते हुए आरोप लगाया कि समिति ने प्रक्रिया में जल्दबाजी की और केवल चयनित लोगों को ही समिति के समक्ष पेश होने के लिए आमंत्रित किया।

● वन संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार, वन संरक्षण अधिनियम विधेयक पर संयुक्त संसद समिति को जनता से 1309 ज्ञापन प्राप्त हुए जो विधेयक की आलोचना कर रहे थे, लेकिन समिति ने इनमें से अधिकांश को अनदेखा किया और विधेयक में सुधार के लिए सिफारिशें देने में असफल रही।

आरोप - उचित निगरानी के बिना बजट पारित करना, जैसे कि वित्त बिल में समस्यात्मक प्रावधानों को शामिल करना, जैसे कि चुनावी बॉन्ड्स

सबूत-

● 2016 से 2023 के बीच औसतन 79% बजट बिना चर्चा के पारित किया गया है। पारंपरिक प्रक्रिया के अनुसार, लोकसभा कुछ मंत्रालयों के बजट पर विस्तार से चर्चा करती है और उन पर अलग से मतदान करती है। बजट चर्चा के लिए आवंटित दिन समाप्त होने के बाद, शेष मंत्रालयों के बजट पर बिना चर्चा के एक साथ मतदान किया जाता है, इस प्रक्रिया को 'गिलोटिन' कहा जाता है। बैठकों की कम संख्या, छोटे बजट सत्र, पारदर्शी जवाबदेही और बहस में रुचि न रखने वाली सरकार के खराब नियोजित एजेंडे के कारण बजट पर विस्तार से कम और कम अनुपात में चर्चा होती है और इसका अधिकतर हिस्सा बिना चर्चा के पारित हो जाता है।

● 2018 के बजट सत्र में सरकार का पूरा बजट एक घंटे के भीतर और अराजकता के बीच, बिना किसी चर्चा के, यानी 100% गिलोटिन पारित हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बजट पर चर्चा और मतदान के लिए आवंटित दिनों में विरोध प्रदर्शन देखा गया क्योंकि अध्यक्ष विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव की मांग को स्वीकार नहीं कर रहे थे।

● 2018 में वित्त विधेयक भी बिना किसी चर्चा के बस अठारह मिनट के भीतर पारित कर दिया गया था।

● 2020 में, वित्त विधेयक बिना किसी चर्चा के एक घंटे के भीतर पारित कर दिया गया, क्योंकि सरकार ने देशव्यापी तालाबंदी (lockdown) लागू करने से कुछ दिन पहले बजट सत्र को समय से पहले ही स्थगित कर दिया था।

● 2017 में, वित्त विधेयक में न्यायाधिकरणों के पुनर्गठन, चुनावी बांड के माध्यम से गुमनाम राजनीतिक दान की अनुमति, स्थायी खाता संख्या (PAN) के लिए आवेदन करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाना आदि के लिए विवादास्पद गैर-वित्तीय प्रावधान शामिल थे।

● साल 2023-24 में भी सदन में विरोध और व्यवधान के बीच पूरा बजट बिना किसी बहस के सिर्फ 8 मिनट में पास हो गया था. विपक्ष अडानी घोटाले पर संयुक्त संसद समिति की मांग कर रहा था. वित्त विधेयक भी बिना किसी बहस के महज 35 मिनट के भीतर पारित हो गया.

● बजट सत्र के बीच में एक अवकाश होता है ताकि स्थायी समितियां प्रत्येक मंत्रालय के बजट की विस्तार से जांच कर सकें। लेकिन सरकार बजट का अध्ययन करने के लिए स्थायी समितियों को कम समय दे रही है। 2016 में 40 दिनों की अवकाश से, 2021 में यह अवकाश घटकर केवल 20 दिन रह गया है।

आरोप - शीतकालीन सत्र **2023** में अभूतपूर्व संख्या में विपक्षी सांसद निलंबित**,** वस्तुतः विपक्ष-विहीन संसद ने विवादास्पद विधेयक पारित किए

सबूत-

● यह अब एक नियमित अभ्यास बन गया है - विपक्ष किसी मुद्दे पर बहस और चर्चा की मांग करता है, सरकार बाधा डालती रहती है और बहस से इनकार करती रहती है, विपक्ष विरोध करता है और व्यवधान डालता है, सरकार इस विरोध के बीच बिना बहस के विधेयकों को पारित करा लेती है । इस बार संसद सुरक्षा उल्लंघन पर बहस की मांग को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के कारण अभूतपूर्व

रूप से 146 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया। यह अब तक निलंबित होने वाले सांसदों की सबसे बड़ी संख्या है। इसका मतलब लगभग दोनों सदनों की सशक्ति का लगभग 20% और असल में पूरी विपक्ष की सशक्ति को है।

● जबकि अधिकांश सांसदों को शीतकालीन सत्र के अंत तक निलंबित कर दिया गया था, कई सांसदों को उनके खिलाफ विशेषाधिकार समिति द्वारा जांच लंबित रहने तक अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था। इस तरह का अनिश्चितकालीन निलंबन गैरकानूनी है क्योंकि नियम स्पीकर या सदन को सांसदों को उस सत्र से परे निलंबित करने का अधिकार नहीं देते हैं जिसमें उन्हें निलंबित किया गया है।

● सांसदों के निलंबन के बाद, कई महत्वपूर्ण विधेयकों को दोनों सदनों में पारित किया गया, जिनमें तीन आपराधिक विधेयक, दूरसंचार विधेयक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए विधेयक आदि शामिल थे।

आरोप - सरकार प्रश्नों के साथ असहज, विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए प्रश्नों को हटा दिया जाता है, मंत्रालय प्रश्नों का उपयोगी उत्तर नहीं देते हैं

सबूत-

● 2023 के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन से निलंबित होने के बाद विपक्षी सांसदों द्वारा पूछे गए करीब 290 प्रश्न हटा दिए गए थे। ऐसे कोई नियम नहीं हैं जो निलंबित सांसदों के प्रश्नों को हटाने का प्रावधान करते हों।

● ऐसा पहली बार नहीं किया गया है। 2015 में ऐसा होने की मीडिया रिपोर्टें हैं और तब से 2020, 2021 और फिर 2023 में ऐसा होने के रिकॉर्ड हैं।

● 2020 में, सरकार ने 2020 के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल को पूरी तरह से हटाने के लिए एक बहाने के रूप में कोविड का भी हवाला दिया, हालांकि विपक्षी दलों के दबाव में, वह केवल लिखित रूप में सवालों के जवाब देने पर सहमत हुई। 2023 के विशेष सत्र के दौरान भी कोई प्रश्नकाल आयोजित नहीं किया गया और किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

● मंत्रालय भी सवालों से बचते हैं, सवालों के विवादास्पद उप-भागों को नजरअंदाज करते हैं, भ्रामक या अधूरे जवाब देते हैं या यूं कह देते हैं की - डेटा उपलब्ध नहीं है। जबकि पिछली सरकारों ने भी सवालों से बचने की कोशिश की है, क्योंकि कोई भी सरकार सवालों के जवाब देने में सहज नहीं होगी, वर्तमान सरकार ने लोगों की जवाबदेही के प्रति विशेष अवमानना का प्रदर्शन किया है।

इस प्रकार, हम भारत के लोग भारत सरकार पर संविधान में निहित लोकतंत्र, न्याय, कानून के शासन और जवाबदेही के आदर्शों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हैं।